

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 31, गुरुवार, शाके 1944-सितम्बर 22, 2022 <i>Bhadra 31, Thursday, Saka 1944- September 22, 2022</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा
अधिसूचनाएं।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 22, 2022

एस.ओ.55 .-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 07-07-2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 7, 2022

यतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 31 के उपबंधों के अधीन, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अध्यधीन रहते हुए, चौबीस मास तक की कालावधि के लिए, और प्रत्येक मामले में बारह लाख रुपये की वित्तीय सीमा तक परामर्शी या वृत्तिक की सेवाएं भाड़े पर लेना आवश्यक है;

और यतः सिविल विमानन विभाग में तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं होने के कारण तकनीकी कार्यों के निष्पादन में विभाग को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनके तकनीकी रूप से विशेषज्ञीय कर्तव्यों का पालन करने के लिए, विभाग को विशेषज्ञीय परामर्श सेवाओं की आवश्यकता है;

अतः, अब, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 31 और राजस्थान लोक

उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन विहित वित्तीय सीमा को लागू किये जाने से सिविल विमानन विभाग को इस शर्त पर छूट देती है कि यह छूट किसी परामर्शी/वृत्तिक की सेवाएं एक वर्ष के लिए भाड़े पर लेने से संबंधित उपापन प्रति वर्ष अठारह लाख रुपये की वित्तीय सीमा तक सीमित होगी।

[सं.एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.